

श्री रवीन्द्र बर्मा : एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बुकिंग के बारे में हमारे पास कई प्रकार की शिकायतें आई हैं। इन को ठोक करने के लिये, इन के इन्तजाम को कैसे कामयाब बना सकते हैं, कैसे कार्यक्रम बना सकते हैं, इन बातों पर विचार करने और सिफारिशें बेश करने के लिये एक कमेटी को नियुक्ति की गई है।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अन्दर जो सेवा-योजना कार्यालय है, उन में शिक्षित और अशिक्षित दोनों के नाम दर्ज होते हैं, उनके भी नाम दर्ज होते हैं, जिनके परिवारों में रोजगार या धन्य है और उनके भी नाम दर्ज होते हैं, जिनके परिवार में कोई रोजगार या धन्य नहीं है। क्या आप कुछ इस तरह की व्यवस्था करेगे कि ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाये, जिनके परिवारों में कोई रोजगार या धन्य नहीं है। उनको सब से पहले प्रायोरिटी दे कर काम पर लगाया जाये ?

श्री रवीन्द्र बर्मा : आप का सवाल मूल प्रश्न में नहीं उठता है, फिर भी सरकार के सामने इस प्रकार की कई सिफारिशें और योजनाएँ आई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी योजनाएं चलाई भी हैं, लेकिन उन के तथुब के आधार पर अभी तक केन्द्रीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है और न इस वक्त इस के बारे में कोई योजना बनाना प्रयोगिक होगा, ऐसा हम मानते हैं :

गुजरात में मलेरिया रोग

†

* 144. श्री धर्म सिंह भाई पटेल :

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में ग्राज तक गुजरात राज्य में जिलावार मलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी रही ;

(ख) क्या गुजरात में मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और यदि हाँ तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) गुजरात में मलेरिया को पूर्णतः कब तक समाप्त किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) मलेरिया के रोगियों के आंकड़े केलेन्डर वर्ष-वार रखे जाते हैं। वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 के दौरान गुजरात में मलेरिया के पोजीटिव रोगियों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। जनवरी-फरवरी 1978 के आंकड़े अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(ख) पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में मलेरिया के रोगियों में निरन्तर वृद्धि होती रही है लेकिन अब तक प्राप्त हुए अन्तिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1977 में वर्ष 1976 की तुलना में मलेरिया के रोगियों में 40 प्रतिशत की कमी बताई गई है।

(ग) यद्यपि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य इस रोग को जड़ से ही समाप्त करना रहा है तथापि अप्रैल 1977से चलाई गई संगोष्ठित कार्य योजना के अन्तर्गत फिलहाल इस रोग की रोकथाम करने का विचार है। इसलिए गुजरात से इस रोग के उन्मूलन की कोई तारीख नहीं बताई जा सकती।

बिबरण

वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 के दौरान गुजरात में मलेरिया के रोगियों का जिलेवार आँकड़ा।

क्रम सं०	जिले का नाम	रोगियों की संख्या		
		1975	1976	1977 (अन्तिम)
1.	अहमदाबाद	81315	135773	75818
2.	अमरेली	12712	12895	9440
3.	बांसकंठा	21884	59709	24934
4.	सुरेन्द्र नगर	31073	83074	34529
5.	बड़ोदा	85815	111760	102335
6.	भावनगर	34797	37307	28962
7.	भडुच	41735	93533	63966
8.	जूनागढ़	21692	25439	16440
9.	खेडा	75816	109839	65961
10.	कच्छ	38657	64039	38129
11.	मेहसाना	28059	67165	28713
12.	गांधी नगर	2291	3579	3295
13.	पंच महल	117178	160986	66951
14.	राजकोट	44633	65687	40535
15.	जामनगर	24343	68859	39086
16.	साबरकंठा	17675	29645	21409
17.	सुरत सिह	83538	65090	44033
18.	वलसर	32452	17450	13091
19.	डंगम	3515	2199	2591
योग		799180	1214028	720218

नोट : वर्ष 1977 के आंकड़े अस्थायी हैं और महामारी विज्ञान की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि 1975 में गुजरात में 7,99,180 मलेरिया के रोगी थे, 1976 में 12,14,028 और 1977 में 7,20,218 रोगी थे। लेकिन आपने गुजरात में मलेरिया रोग को पूर्णतः उन्मूलन करने का कोई स्पष्ट साल या वर्ष का उल्लेख नहीं किया है। इस का कारण क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि गुजरात में मलेरिया रोग को कब तक पूर्णतः उन्मूलन किया जाएगा?

श्री राज नारायण : श्रीमन् मैंने पहले ही यह कह दिया है कि गुजरात से मलेरिया रोग पूर्णरूपेण उन्मूलित कब तक हो जाएगा, इसका ठीक उत्तर अभी प्राप्त नहीं है और इसलिए यह अभी नहीं बताया जा सकता है।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या कारण है ?

श्री राज नारायण : जितनी दूर तक यह देश श्रमती इन्दिरा गांधी की शक्ति का उन्मूलन करेगा उतनी दूर तक मलेरिया का उन्मूलन होगा।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : आप ने भाग (ग) में यह कहा है कि यद्यपि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य इस रोग को जड़ में ही समाप्त करना रहा है तथापि अप्रैल, 1977 से चलाई गई संशोधित कार्य योजना में अन्तर्गत फिलहाल इस रोग की रोकथाम करने का विचार है। इस संशोधित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और गुजरात में एक साल में कितना खर्च किया जाता है ?

श्री राज नारायण : सदन जरा शान्त रहे। मैं निवेदन कर दूँ कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिस का उत्तर मैं यथाशक्ति न दूँ। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मैं सदन को यह बता दूँ कि 1 अप्रैल,

1977 से हमने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित कार्य योजना चलाई है। इस योजना के अधीन राज्य को कीटनाशी और मलेरिया-रोधी दवाईयाँ पर्याप्त मात्रा में दी गईं। इस बात का भी सुनिश्चय किया गया कि आने वाले मलेरिया के मौसम के लिए कीटनाशी और मलेरिया-रोधी दवाईयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी। 1978 की जरूरतों के लिए राज्य के पास बचा निश्चलित स्टॉक है :

	जितनी जरूरत है	जितना स्टॉक है
डी०डी०	50 मी० टन	117.66
टी०		मी० टन
बी०एच०	3146 मी० टन	2282.92
सी०		मी० टन

मालाशियन 25 प्रतिशत.. (अधुषधान)
1545 टन की अतिरिक्त मात्रा राज्य के लिए नियत कर दी गई है और इसकी पूर्ति शीघ्र कर दी जाएगी। (अधुषधान)

PROF. P. G. MAVALANKAR: Will you kindly ask the Minister to place it on the table of the House (Interruptions)

MR. SPEAKER: You may please place it on the Table of the House.

श्री राज नारायण : रोगियों को लावा-रोधी औषधियाँ आसानी से उपलब्ध करने और बीमारी की अवधि कम करने और मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए राज्य में 19,848 औषधि वितरण केन्द्र और 12,256 बुखार उपचार डिपो स्थापित कर दिए गए हैं। 1978 के दौरान और अधिक ऐसे केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।

श्री अहमद एम० पटेल : श्री मंत्री जी ने बताया है कि 1977 में 40 परसेंट मलेरिया कम हुआ। क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि अगले डेढ़ साल में यह पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया जाएगा ?

श्री राज नारायण : जैसा मैंने अभी बताया हमारी नीति यह है कि मलेरिया को कंट्रोल करें, इसके प्रसार को बढ़ने न दें और इससे जो रोग होता है वह न होने दें। लेकिन यह पूर्ण-रूपेण कब तक हों जाएगा यह हम नहीं बता सकते हैं।

SHRI VINODBHAI B. SHETH: As we know, the open drainage is a breeding ground for mosquitoes which are responsible for spreading malaria. In this connection, did the Ministry of Health approach the LIC and other financial institutions to grant loans liberally to the State Governments or the municipalities or the municipal corporations to enable them to have underground drainages? I know that the Jamanagar municipality had applied to LIC for loan for this purpose, but they have not been granted. What are you going to do to render such help for underground drainages, particularly in Gujarat?

श्री राज नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्मानित सदस्य का सुझाव सुना है और जो कुछ सम्भव हो सकेगा, केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी। मगर परेशानी यह है कि हम राज्य सरकारों को कहते हैं कि और जो और इस ढंग से काम करो मगर राज्य सरकारें करती नहीं हैं।

श्री सोमजीभाई डामोर : माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकार की नीति मलेरिया को नाबूद करने की है और इसके बारे में बे मेजर्स ले रहे हैं जिससे कि यह कंट्रोल हो सके। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या मेजर्स ले रहे हैं ?

श्री राज नारायण : इस मामले में राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा 1-4-77 से कार्य की एक संशोधित योजना कार्यान्वित की जा रही है। यद्यपि इस योजना का अंतिम उद्देश्य इस रोग का उन्मूलन करना है, फिलहाल इसकी रोकथाम करने का विचार है। निम्नलिखित राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों ने संशोधित योजना को स्वीकार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश

MR. SPEAKER: No, no. Please confine your reply to Gujarat. Please do not widen the scope.

श्री राज नारायण : सब पूछा है। उत्तर प्रदेश ने भी कल शाम उसको स्वीकार कर लिया है

श्री हुकम चन्द कछवाय : महाराष्ट्र का भी बताएं, तमिलनाडु का भी बताएं सब का बताएं।

श्री राज नारायण : मैं जानता था कि जानना चाहेंगे और पूछेंगे। आधा मिनट में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने भी स्वीकार कर लिया है कल शाम। मणिपुर मेघालय आदि ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है। इस मामले में स्वीकृति प्रदान करने के लिए इन राज्यों से जिन्होंने स्वीकृति नहीं दी है लिखा-पढ़ी की जा रही है। संशोधित कार्य योजना के वर्तमान उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- 1 मलेरिया के कारण होने वाली मोतों को रोकना
- 2 औद्योगिक और हरित अन्ति को बनाए रखना
- 3 प्राप्त की गई उपलब्धियों को बनाए रखना

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिट का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है।

पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटों का पुनर्गठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।

राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयां (डी०डी०टी०) बी०एच०सी० (मेलारिजिन) की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है / की जा रही है। जहां रोग वाहकों पर डी०डी०टी० का कोई असर नहीं होता उन यूनिटों/जिलों को बैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं।

उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति हजार जन संख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को मलेरिया रोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं / की जा रही हैं। शोधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिए शोधित वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में परिजीवियों पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ वहां पर कुनीन जैसी बैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाइयें सप्लाई की गई हैं।

MR. SPEAKER: You are making a speech every time. You may lay it if it is a long reply.

श्री राज नारायण : मैं इसको सदन पटल पर रख दूंगा। माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि पहली अप्रैल से हमने नई योजना क्या चलाई है। उसके बारे में हमने बता . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने उत्तर दे दिया है।

श्री मोती भाई धार० चौधरी : गुजरात में कई भाग ऐसे हैं जहां गांव के गांव मलेरिया से ग्रस्त होते हैं। जिन गांवों में पीने के पानी

की सुविधा नहीं है वहां गन्दा पानी पिया जाता है। जो गांव पूरे के पूरे मलेरिया से ग्रस्त हैं उनके लिए क्या कोई स्पेशल योजना बनाई जाएगी और अगर कम डी डी टी का छिड़काव किया जाता है और वह असुद्ध होती है तो पूरा और शुद्ध डी डी टी का छिड़काव करने की व्यवस्था की जाएगी और क्या इस चीज की जांच की जाएगी ?

श्री राज नारायण : हमारी भी मुसीबत है। हमारे जो बरिष्ठ सदस्य हैं उन से हमने निवेदन किया है, कई बार पत्र लिखे हैं कि पीने का पानी वास्तव में स्वास्थ्य विभाग के पास रहना चाहिये। दुनिया के अन्य हिस्सों में है। हमारे देश में कई राज्यों में है। लेकिन दुर्भाग्य से 1969 से जब से कांग्रेस टूटी यह सही दूसरी जगह चला गया। अब हमारे पास वह विभाग नहीं है।

MR. SPEAKER: Next question.—
Shri Samar Mukherjee.

PROF. P. G. MAVALANKAR: The Minister has said something which is not a fact. In his answer he has tried to discredit the State Government of Gujarat saying that the State Government is not responding, whereas the situation is totally different. Moreover, the incidence of Malaria is very high in Ahmedabad.

MR. SPEAKER: Q. No. 145. (Interruptions)

Mr. Mavalankar, I have called Q No. 145. (Interruptions)

श्री राज नारायण : मान्यवर, मैंने गुजरात सरकार के बारे में नहीं कहा, माननीय सदस्य ने सम्भवतः गलत सुना है। गुजरात सरकार ने हमारे निर्देशों का पालन किया है। जिन राज्यों के बारे में मैंने पढ़ा उसके बारे में कहा कि कुछ राज्यों ने हमारी योजना को पूर्णतः माना और कल शाम आते आते अधिकारियों ने मान लिया है।